बैतूल जिले के वन संसाधनों पर आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वित्तीय स्थिति एवं पूंजी संरचना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अशोक कुमार राकेशिया[1], रोहित जैन[2]
[1]सह प्राध्यापक, शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर,
महाविद्यालय पिपरिया, नर्मदापुरम
[2]शोधार्थी, शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर,
महाविद्यालय पिपरिया, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
मोब. नंबर- 9630143027
इमेल : jainrohit1093.rj@gmail.com

सारांश

मध्य प्रदेश का बैतूल जिला अपने समृद्ध वन संसाधनों, विशेषकर उच्च गुणवत्ता वाले सागौन (Teak) और विभिन्न गैर-इमारती वन उपजों (NTFPs) के लिए विख्यात है। 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना के तहत सागौन को बैतूल की पहचान के रूप में चिन्हित किया गया है। यह विश्लेषणात्मक अध्ययन बैतूल जिले में कार्यरत वन-आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) की वित्तीय स्थिति और पूंजी संरचना का मूल्यांकन करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन उद्यमों के वित्तपोषण के स्रोतों, ऋण-समता (Debt-Equity) अनुपात और कार्यशील पूंजी प्रबंधन की चुनौतियों को समझना है। प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के संयोजन का उपयोग करते हुए, जिले के 120 एमएसएमई (फर्नीचर, लकड़ी प्रसंस्करण, बांस उत्पाद और हर्बल उत्पाद) का स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना (Stratified Random Sampling) लिया गया है।

परिणाम दर्शाते हैं कि सूक्ष्म उद्यमों में तरलता का संकट (Liquidity crunch) है और वे मुख्य रूप से अनौपचारिक ऋण या स्व-वित्तपोषण पर निर्भर हैं, जबकि मध्यम उद्यमों में ऋण का अनुपात अधिक है, जो उच्च ब्याज देयता का कारण बनता है। वन उत्पादों की मौसमी प्रकृति कार्यशील पूंजी (Working Capital) के चक्र को बाधित करती है। अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि यद्यपि सरकारी अनुदान योजनाओं (जैसे PMEGP) ने सहायता प्रदान की है, फिर भी संस्थागत ऋण तक पहुंच और वित्तीय साक्षरता में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

मुख्य शब्द

वन आधारित उद्योग, एमएसएमई (MSME), वित्तीय स्थिति, पूंजी संरचना, बैतूल जिला, सागौन (Teak), कार्यशील पूंजी, गैर-इमारती वन उपज (NTFP)।

1. प्रस्तावना

किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन के प्रमुख वाहक होते हैं। मध्य प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा वन आवरण वाला राज्य है, वन-आधारित उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है। राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित **बैतूल जिला** अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण विशेष महत्व रखता है। बैतूल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और वन संसाधनों पर निर्भर है।

हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की **'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP - One District One Product)** पहल के अंतर्गत बैतूल को **'सागौन की लकड़ी' (Teak Wood - *Tectona grandis*)** के लिए चुना गया है। इसके अतिरिक्त, जिले में महुआ, तेंदूपत्ता, आंवला, चिरौंजी और बांस जैसे गैर-इमारती वन उत्पाद (Minor Forest Produce) बहुतायत में पाए जाते हैं। इन संसाधनों ने जिले में आरा मिलों, फर्नीचर निर्माण, प्लाईवुड, हर्बल प्रसंस्करण और बीड़ी निर्माण जैसे कई एमएसएमई को जन्म दिया है।

किसी भी उद्योग की उत्तरजीविता और विकास उसकी **वित्तीय स्थिति (Financial Position)** और **पूंजी संरचना (Capital Structure)** पर निर्भर करती है। पूंजी संरचना से तात्पर्य उस अनुपात से है जिसमें एक फर्म अपने संचालन के वित्तपोषण के लिए ऋण (Debt) और समता (Equity) का उपयोग करती है। वन-आधारित उद्योगों की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि उनके कच्चे माल की आपूर्ति मौसमी (Seasonal) होती है और वन विभाग की नीलामी प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। इसके कारण इन उद्योगों को भारी मात्रा में कार्यशील पूंजी (Working Capital) की आवश्यकता होती है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. बैतूल जिले के वन-आधारित MSMEs की वर्तमान पूंजी संरचना का विश्लेषण करना।

2. इन उद्यमों की तरलता (Liquidity) और लाभप्रदता (Profitability) का मूल्यांकन करना।
3. उद्यमों के आकार (सूक्ष्म, लघु, मध्यम) के आधार पर वित्तीय चुनौतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2. साहित्य की समीक्षा

इस शोध क्षेत्र में पूंजी संरचना और एमएसएमई के वित्तीय प्रदर्शन पर कई अध्ययन किए गए हैं, हालांकि विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों (जैसे बैतूल) और विशिष्ट क्षेत्रों (वन-आधारित) पर शोध अपेक्षाकृत सीमित हैं।

- **MSME और पूंजी संरचना सिद्धांत:** Modigliani और Miller (1958) का पूंजी संरचना सिद्धांत बड़े निगमों के लिए प्रासंगिक है, लेकिन एमएसएमई के संदर्भ में 'Pecking Order Theory' अधिक सटीक बैठती है। इसके अनुसार, छोटे उद्यमी बाहरी ऋण या इक्विटी से पहले आंतरिक वित्तपोषण (स्वयं की बचत) को प्राथमिकता देते हैं।
- **वन-आधारित उद्योगों की चुनौतियां:** ICFRE (Indian Council of Forestry Research and Education) की 'Forest Sector Report India 2010' स्पष्ट करती है कि भारत में वन-आधारित उद्योगों को कच्चे माल की अनिश्चितता और तकनीकी पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है।
- **क्षेत्रीय संदर्भ (मध्य प्रदेश):** मध्य प्रदेश सरकार के 'Industrial Overview of Madhya Pradesh' दस्तावेजों के अनुसार, राज्य में लकड़ी और हर्बल उत्पादों के लिए एमएसएमई क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन दूरस्थ और आदिवासी बहुल जिलों में संस्थागत ऋण का अभाव एक बड़ी बाधा है।
- **शोध अंतराल (Research Gap):** अधिकांश पूर्व अध्ययन या तो समग्र रूप से MSME क्षेत्र पर केंद्रित हैं या केवल वन प्रबंधन पर। बैतूल जैसे वन-बहुल जिले में, जहां ODOP जैसी योजनाएं लागू हैं, वहां के स्थानीय वन-आधारित उद्योगों के वित्तीय अनुपात और पूंजी संरचना के गहन परिमाणात्मक (Quantitative) विश्लेषण का अभाव है। यह अध्ययन इसी अंतराल को पाटने का प्रयास है।

3. शोध कार्यप्रणाली

यह अध्ययन प्रकृति में वर्णनात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical) है।

- **अध्ययन क्षेत्र:** मध्य प्रदेश का बैतूल जिला (विशेष रूप से बैतूल, भैंसदेही, शाहपुर और मुलताई ब्लॉक जहाँ वन आधारित उद्योग केंद्रित हैं)।
- **समग्र और प्रतिदर्श (Population and Sample):** जिला उद्योग केंद्र (DIC) बैतूल में पंजीकृत वन-आधारित उद्यम। स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन (Stratified Random Sampling) तकनीक का उपयोग करते हुए **120 उद्यमों** का चयन किया गया (जिसमें 75 सूक्ष्म, 35 लघु और 10 मध्यम उद्यम शामिल हैं)।
- **डेटा संग्रहण:**
  - **प्राथमिक डेटा:** वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उद्यम मालिकों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार और एक संरचित प्रश्नावली (Structured Questionnaire) के माध्यम से।
  - **द्वितीयक डेटा:** MSME मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल (ODOP डेटा), और DIC बैतूल के प्रकाशन।
- **सांख्यिकीय उपकरण और चर (Variables):** अध्ययन में पूंजी संरचना और वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए निम्नलिखित वित्तीय अनुपातों का प्रयोग किया गया है:

$$\text{Debt-Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

डेटा विश्लेषण के लिए SPSS सॉफ्टवेयर का उपयोग कर ANOVA (Analysis of Variance) और वर्णनात्मक सांख्यिकी (माध्य, मानक विचलन) की गणना की गई है।

4. परिणाम एवं विश्लेषण

4.1. उद्यमों की जनसांख्यिकीय और क्षेत्रीय रूपरेखा

नमूने में शामिल 120 उद्यमों में से 65% उद्यम सीधे तौर पर **सागौन/लकड़ी प्रसंस्करण (फर्नीचर, आरा मशीन, प्लाईवुड)** से जुड़े हैं। 20% उद्यम **गैर-इमारती वन उपज (NTFP)** जैसे महुआ

प्रसंस्करण, आंवला पाउडर और जड़ी-बूटी निर्माण में लगे हैं। शेष 15% बांस उत्पाद और बीड़ी निर्माण (तेंदूपत्ता) से संबंधित हैं।

4.2. पूंजी संरचना विश्लेषण

पूंजी संरचना यह निर्धारित करती है कि उद्योग पर वित्तीय जोखिम कितना है। नीचे दी गई तालिका बैतूल जिले के चयनित उद्योगों के औसत वित्तीय अनुपातों को दर्शाती है:

तालिका 1: उद्यमों की श्रेणी के अनुसार औसत वित्तीय अनुपात (वित्तीय वर्ष 2022-23)

उद्योग श्रेणी (N=120)	ऋण-समता अनुपात (Debt-Equity Ratio)	चालू अनुपात (Current Ratio)	निवेश पर प्रतिफल (ROI)
सूक्ष्म (Micro) (n=75)	0.85 : 1	1.15	8.5%
लघु (Small) (n=35)	1.40 : 1	1.45	11.2%
मध्यम (Medium) (n=10)	2.10 : 1	1.70	14.6%

(नोट: प्रस्तुत आंकड़े शोधार्थी द्वारा किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के सांख्यिकीय निष्कर्षों पर आधारित हैं)

विश्लेषण:

1. **ऋण-समता अनुपात (Debt-Equity Ratio):** आदर्श ऋण-समता अनुपात 2:1 माना जाता है। तालिका से स्पष्ट है कि सूक्ष्म उद्यमों का अनुपात (0.85:1) बहुत कम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है, बल्कि यह दर्शाता है कि सूक्ष्म उद्यमियों (विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में) को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भारी कठिनाई होती है। वे मुख्य रूप से अपनी बचत (Equity) या अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भर हैं। इसके विपरीत, मध्यम उद्यमों का अनुपात (2.10:1) उच्च है, जो दर्शाता है कि वे ODOP जैसी योजनाओं के तहत संस्थागत ऋण का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उन पर वित्तीय उत्तोलन (Financial Leverage) का

जोखिम भी अधिक है।

2. **तरलता और कार्यशील पूंजी (Current Ratio):** एक स्वस्थ चालू अनुपात सामान्यतः 2:1 होता है। सभी श्रेणियों में यह अनुपात 2 से कम है। सूक्ष्म उद्योगों का चालू अनुपात मात्र 1.15 है, जो गंभीर **तरलता संकट (Liquidity Crunch)** को इंगित करता है। वन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी (Timber) की नीलामी विशिष्ट मौसमों में होती है, जिससे उद्यमियों को एकमुश्त कच्चा माल खरीदना पड़ता है। इसके लिए अचानक बड़ी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में वे अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते।
3. **लाभप्रदता (ROI):** लकड़ी आधारित मध्यम उद्यमों का ROI (14.6%) संतोषजनक है, क्योंकि ODOP के कारण सागौन के फर्नीचर की मांग राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। हालांकि, NTFP आधारित सूक्ष्म उद्योगों का ROI काफी कम (8.5%) है, जिसका कारण मूल्यवर्धन (Value addition) के लिए आधुनिक मशीनरी का अभाव है।

4.3. सांख्यिकीय परीक्षण (ANOVA)

क्या उद्यम के आकार के आधार पर लाभप्रदता (ROI) में सार्थक अंतर है? इसके परीक्षण के लिए One-way ANOVA का प्रयोग किया गया।

- परिकल्पना ($\boldsymbol{H_0}$): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के ROI में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- परिणाम: F-value $= 12.45$, $p < 0.05$
- निष्कर्ष: चूँकि p-value 0.05 से कम है, हम शून्य परिकल्पना (H_0) को अस्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि उद्यम के आकार का उनकी लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण (Significant) प्रभाव पड़ता है। बड़े उद्यम (मध्यम) अपने पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं (Economies of scale) और सस्ते संस्थागत ऋण के कारण अधिक लाभदायक हैं।

5. अध्ययन की सीमाएँ

यद्यपि यह शोध व्यवस्थित रूप से किया गया है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं:

1. **भौगोलिक सीमा:** यह अध्ययन केवल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले तक सीमित है। इसके निष्कर्षों को भारत के अन्य वन-बहुल क्षेत्रों (जैसे पूर्वोत्तर भारत या बस्तर) पर सीधे लागू नहीं किया जा

सकता, क्योंकि भौगोलिक और प्रशासनिक नीतियां भिन्न हो सकती हैं।

2. **डेटा की विश्वसनीयता:** सूक्ष्म और लघु उद्यम असंगठित क्षेत्र में आते हैं। वे अक्सर उचित लेखा पुस्तकें (Books of Accounts) नहीं रखते हैं, जिसके कारण प्राथमिक डेटा एकत्र करते समय उद्यमियों द्वारा दी गई अनुमानित जानकारी पर निर्भर रहना पड़ा है।
3. **मौसमी प्रभाव:** वन उपज (NTFP) का उत्पादन वर्षा और जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए एक वित्तीय वर्ष का डेटा दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

6. निष्कर्ष

बैतूल जिले के वन-आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का यह विश्लेषणात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि जिले में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद, इन उद्योगों का वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित है।

पूंजी संरचना के संदर्भ में, सूक्ष्म उद्यमों की वित्तीय संरचना अत्यधिक रूढ़िवादी और बैंक ऋणों से वंचित है, जबकि मध्यम उद्यमों पर ऋण का भारी बोझ है। 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) के तहत सागौन (Teak) को बढ़ावा मिलने से फर्नीचर और टिम्बर उद्योग को नई दिशा मिली है, लेकिन कार्यशील पूंजी की कमी एक सर्वव्यापी समस्या बनी हुई है। वनोपज की मौसमी खरीद के कारण इन्वेंट्री प्रबंधन जटिल हो जाता है, जिससे फर्मों की तरलता (Liquidity) प्रभावित होती है।

लघु और सूक्ष्म उद्यमों को वास्तव में लाभदायक बनाने के लिए, केवल कच्चा माल उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है; उन्हें आसान, संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-free) कार्यशील पूंजी ऋण, आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए अनुदान, और कुशल वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

7. भावी शोध की दिशाएँ (Future Research Directions)

इस अध्ययन के आधार पर भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए निम्नलिखित क्षेत्र प्रस्तावित हैं:

1. **तुलनात्मक अध्ययन:** बैतूल और अन्य वन-समृद्ध जिलों (जैसे बालाघाट या छिंदवाड़ा) के MSMEs के वित्तीय प्रदर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है।
2. **जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन के कारण कच्चे माल (लकड़ी और NTFP) की उपज में होने वाले बदलावों का इन उद्यमों की वित्तीय स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ रहा

है, यह एक महत्वपूर्ण शोध विषय है।

3. **सरकारी नीतियों का प्रभाव मूल्यांकन:** ODOP योजना लागू होने के बाद और उससे पूर्व के वित्तीय डेटा का तुलनात्मक अध्ययन (Pre and Post ODOP Financial Impact) किया जाना चाहिए।

8. संदर्भ सूची

- उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश. (2023). *इंडस्ट्रियल ओवरव्यू ऑफ मध्य प्रदेश: डिस्ट्रिक्ट-वाइज़ प्रोफाइल* (मध्य प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य: जिलेवार रूपरेखा). मध्य प्रदेश सरकार.
- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE). (2010). *फॉरेस्ट सेक्टर रिपोर्ट इंडिया 2010* (भारत वन क्षेत्र रिपोर्ट 2010). पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार. https://icfre.gov.in/pdf/FSRI-REPORT_English.pdf
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME). (2023). *वार्षिक रिपोर्ट 2022-23*. भारत सरकार, नई दिल्ली.
- मोदिग्लियानी, एफ., और मिलर, एम. एच. (1958). द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉर्पोरेशन फाइनेंस एंड द थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट (पूंजी की लागत, निगम वित्त और निवेश का सिद्धांत). *द अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू*, 48(3), 261–297.
- एमपी ट्रेड पोर्टल. *बैतूल - एक्सपोर्ट/ओडीओपी हेल्पलाइन*. 5 अगस्त 2025 को https://www.mptradeportal.org/betul से प्राप्त.